

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 4427/2026**

अनुभव

.....प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव (गृह),

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

.....विपक्षी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता	: रमाकर शुक्ला
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	: शा.अ.

न्यायालय संख्या - 12**माननीय न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह**

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. के निवेदनों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर मुकदमा अपराध संख्या 251/2026, अंतर्गत धारा 309(4), 317(2), 61(2) भा.न्या.सं. (392, 411, 120ख भा.दं.सं.); थाना-कोतवाली नगर, जिला-सुल्तानपुर आरोप में प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्र.सू.रि. में प्रार्थी का नाम नहीं है और उसे सिर्फ सह-अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस मामले में फंसाया गया है। उनका निवेदन है कि प्रार्थी का एक आपराधिक इतिहास है, जिसके बारे में जमानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर 15 में उल्लेख किया गया है। प्रार्थी 9.5.2026 से जेल में निरुद्ध है और अगर उसे जमानत प्रदान की जाती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और कहा कि प्रार्थी उक्त अपराध में शामिल है, इसलिए वह जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों को सुनने और अभिलेख के अवलोकन के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि प्र.सू.रि. में प्रार्थी का नाम नहीं था और उसका नाम सह-अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति बयान में सामने आया; जमानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर 15 में प्रार्थी के आपराधिक इतिहास के बारे में बताया गया है; प्रार्थी 9.5.2026 से जेल में निरुद्ध है और उसने वचन दिया है कि अगर उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों, आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सज़ा की गंभीरता, साक्ष्यों की प्रकृति, आरोपों के समर्थन में न्यायालय की प्रारम्भिक संतुष्टि, सज़ा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत देने योग्य मामला मानता हूँ।

उपरोक्त वर्णित अपराध में शामिल प्रार्थी **अनुभव** को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करे:-

1. प्रार्थी विवेचना या परीक्षण के दौरान साक्षियों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. प्रार्थी को यह वचन देना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथियों पर सुनवाई स्थगन की मांग नहीं करेगा। उसे नियत प्रत्येक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तिथि पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए उपस्थित रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस कारण के उपस्थित नहीं रहता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है।

3. प्रार्थी को (i) वाद को शुरू करने, (ii) आरोप निर्धारित करने और (iii) धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा; और
4. अगर प्रार्थी परीक्षण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और प्रार्थी उस उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत विधि अनुरूप कार्यवाही शुरू करेगा।

संबंधित न्यायालय प्रतिभुओं की पहचान, हैसियत और रिहायशी पते के साक्ष्यों की जांच करेगी। अगर उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो अवर न्यायालय के पास ज़मानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने का अधिकार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस ज़मानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी तरह का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह)

25 जून 2026

राम मूर्ति